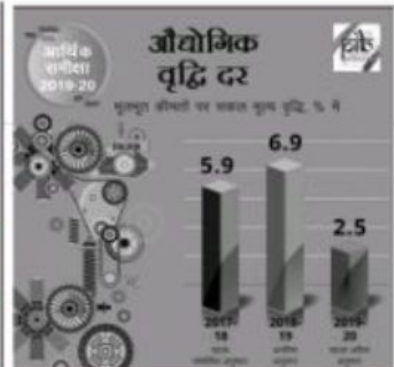


- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अपनी किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना को स्वीकार किया? - **प्रथम औद्योगिक नीति**
- औद्योगिक उद्यम के उस प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है, जिसमें स्थायी पूंजी निवेश 100 करोड़ रुपये से अधिक और 1000 रुपये करोड़ रुपये अधिक न हो? - **मेगा प्रोजेक्ट**
- औद्योगिक उपक्रम के अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में स्थायी पूंजी निवेश कितना होना चाहिए? - **1000 करोड़ रुपये से अधिक**
- भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल, 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री द्वारा घोषित की गई थी। उनका क्या नाम है? - **डॉ. जयामाप्रसाद मुखर्जी**
- औद्योगिक नीति, 1948 में भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की संकल्पना को स्वीकार किया गया? - **मिश्रित अर्थव्यवस्था**
- भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 1 अप्रैल, 1956 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? - **समाजवादी समाज की स्थापना**
- दिसंबर 1977 में तत्कालीन उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज द्वारा तीसरी औद्योगिक नीति घोषित की गई। इसके तहत आर्थिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण, लघु उद्योगों के दायरे में वृद्धि, बड़े उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबंध के साथ किस प्रकार के क्षेत्र की अवधारणा को प्रचलन में लाये जाने का प्रमुख प्रावधान था? - **अति लघु क्षेत्र**
- किस औद्योगिक नीति में **जिला उद्योग केंद्र** की अवधारणा को प्रचलन में लाया गया? - **औद्योगिक नीति, 1977**
- औद्योगिक नीति, 1977 में लघु क्षेत्र के लिए संरक्षित उद्योगों की संख्या 108 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? - **825**
- पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जुलाई 1980 में जारी चौथी औद्योगिक नीति के तहत किस केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई? - **केंद्रीय औद्योगिक केंद्र**
- तत्कालीन उद्योग मंत्री अजीत सिंह द्वारा मई 1990 में घोषित पांचवीं औद्योगिक नीति में लघु तथा कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया। इसमें विकास की कौन-सी रणनीति अपनायी गई? - **उदारीकरण के साथ तीव्र औद्योगिक विकास**
- छठी औद्योगिक नीति 24 जुलाई, 1991 को तत्कालीन उद्योग मंत्री पी.जे. कुरियन द्वारा घोषित की गई। इस नीति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? - **औद्योगिक एवं लाइसेंसिंग नीति, 1991**
- 1991 के पहले औद्योगिक एवं लाइसेंसिंग नीति दोनों अलग-अलग घोषित की जाती थीं। पहली बार दोनों की घोषणा संयुक्त रूप में किस नीति में की गई? - **छठी औद्योगिक नीति**
- औद्योगिक एवं लाइसेंस नीति, 1991 के मुख्य आधार उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण हैं। इसके तहत केवल 3 उद्योगों को ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा। ये क्षेत्र कौन-कौनसे हैं? - **रेलवे परिवहन, परमाणु ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा खनिज**



### उद्यमवृत्ति (या उद्यम)

आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन का एक साधन, उत्पादन का संचालक-आवश्यक पूंजी जुटाना, व्यापार का संचालन, प्रबंधन, व्यापार के अनिवार्य फैसले, जॉइंटम उठाना, उसकी सफलता से लाभ और असफलता का नुकसान उठाना उद्यमवृत्ति या उद्यम (Enterpr-eneurship or Enterprise) कहलाता है। जोसेफ शुम्पीटर पूंजीवादी व्यवस्था में नवोत्पाद को उद्यमी का अनिवार्य काम मानते हैं।

### संरक्षण

संरक्षण (Protection) एक ऐसी नीति है, जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से आयात कर लगाकर घरेलू उत्पादकों को आर्थिक सहायता प्रदान करके घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

### शिशु उद्योग तर्क

नए उद्योगों को प्रारम्भिक विकास की अवस्था में विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए संरक्षण प्रदान करने संबंधी तर्कों को शिशु उद्योग तर्क (Infant Industry Argument) की संज्ञा प्रदान की जाती है।

- नई औद्योगिक नीति, 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को आकर्षित करने के लिए उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी इक्विटी की सीमा स्वचालित प्रक्रिया के तहत 40 प्रतिशत से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? - **मात्र 51 प्रतिशत**
- 1970 में लागू एकाधिकारात्मक एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP Act) में किस औद्योगिक नीति में परिवर्तन कर निर्धारित पूंजी निवेश सीमा को समाप्त कर दिया गया? - **औद्योगिक नीति, 1991**
- किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है? - **1956 की**
- भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू तथा विदेशी कम्पनियों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एमआरटीपी अधिनियम के स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित किया गया? - **वर्ष 2002**
- केंद्र सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम लाने का निर्णय किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया? - **विजय राघवन समिति**
- 14 जनवरी, 2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद अस्तित्व में आये प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत 14 अक्टूबर, 2003 को किस आयोग का गठन किया गया? - **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)**
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में एक चेयरपर्सन के अलावा कितने सदस्य होते हैं? - **छह**
- 1960 में निवेश कसौटी के आधार पर उद्योगों को लघु उद्योग, भारी उद्योग तथा मध्यम उद्योग में वर्गीकृत किया जाता था। 1977 की औद्योगिक नीति में किस एक नई श्रेणी की शुरुआत की गई? - **अति लघु क्षेत्र**
- किस समिति ने 1997 में लघु उद्योगों में निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की थी? - **आबिद हुसैन समिति**
- सूक्ष्म उद्योगों में निवेश की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये होती है। लघु उद्योगों में निवेश की अधिकतम सीमा कितनी होती है? - **25 लाख से अधिक और 5 करोड़ रुपये से कम**
- मध्यम उद्योगों में निवेश की सीमा 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक तथा 10 करोड़ रुपये से कम होती है। भारी उद्योगों में निवेश की सीमा कितनी होती है? - **10 करोड़ रुपये या इससे अधिक**
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एक सांविधिक संगठन के रूप में किस आयोग का गठन किया गया? - **खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)**
- बाजार में बेचे जा रहे खादी की शुद्धता की गारंटी को सुनिश्चित करने और बाजार में खादी की विशिष्ट पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से 'खादी मार्क विनियम 2013' को कब अधिसूचित किया गया? - **22 जुलाई, 2013 को**
- भारत विश्व का सर्वाधिक कपूर (नारियल जट्टा) उत्पादन करने वाला देश है, जो विश्व में पैदा होने वाले कुल कपूर रेशों का कितना प्रतिशत है? - **80 प्रतिशत से अधिक**
- कपूर उद्योग के समग्र सतत विकास के संवर्धन तथा इस परंपरागत उद्योग में लगे कामगारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में कपूर अधिनियम 1953 के अधीन किस संस्था की स्थापना की गई है? - **कपूर बोर्ड**

## पेटेंट

पेटेंट नवीनता को प्रोत्साहित करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है। जब कोई वैज्ञानिक या आविष्कारक कोई ऐसी नवीनता खोज करता है, जिसका कि औद्योगिक या व्यापारिक उपयोग हो सकता है तो वह अपनी खोज, आविष्कार, तकनीक और ज्ञान को चोरी तथा नकल से बचाने के लिए पेटेंट कराता है। सरकार कानूनी रूप से आविष्कारक को पेटेंट अधिकार प्रदान करती है।

## प्रक्रिया पेटेंट

प्रक्रिया पेटेंट (Process Patent) के तहत किसी उत्पाद के निर्माण की विधि पर पेटेंट प्रदान किया जाता है। इसके तहत अनुसंधानकर्ता को पेटेंट का अधिकार प्रदान किया जाता है। इसका संबंध नई प्रौद्योगिकी से है। किसी भी नई तकनीकी पर भी पेटेंट लिख जा सकता है। इस प्रकार के पेटेंट का अर्थ यह है किसी भी व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को बनाने के लिए उसी प्रक्रिया या तकनीकी से उत्पाद का नहीं बना सकती जिस प्रक्रिया से किसी उत्पाद को पहले ही किसी कम्पनी द्वारा बनाया जा चुका है। इस पेटेंट के तहत किसी उत्पाद को बनाने की विधि की चोरी नहीं की जा सकती।

## उत्पाद पेटेंट

उत्पाद पेटेंट (Product Patent) के अंतर्गत उत्पाद पर पेटेंट प्रदान किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को हबहु नकल का उत्पाद नहीं बना सकती अर्थात् दो उत्पादों की डिजाइन एक जैसी नहीं हो सकती। यह अंतर उत्पाद की पैकिंग, नाम, रंग, आकार और स्वाद आदि का होता है। यही कारण है कि आपने बाजार में कई प्रकार के डिब्बे देखते होंगे, लेकिन उनमें से किसी भी दो कम्पनी के उत्पाद एकदम एक जैसे नहीं देखें होंगे। ऐसा उत्पाद पेटेंट के कारण ही होता है। इसका उत्पाद विधि से कोई संबंध नहीं होता है।



## औद्योगिक क्षेत्र

- सरकार द्वारा देश में लघु उद्योगों की वृद्धि का संवर्धन, सहायता तथा पोषण करने के उद्देश्य से किस वर्ष राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) की स्थापना की गई थी?  
- वर्ष 1955
- एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट, 2018-19 के अनुसार, भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या 6.34 करोड़ है। आलोच्य अवधि में देश की जीडीपी में इनका कितना प्रतिशत योगदान रहा?  
- लगभग 30 प्रतिशत (जीवीए में 31.8%)
- भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश (88.99 लाख) में हैं। इस मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन-कौन से राज्य हैं?  
- पश्चिम बंगाल (88.67 लाख) और तमिलनाडु (49.99 लाख)
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में देशभर में 11.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इन उद्यमों में सर्वाधिक रोजगार किस राज्य में उपलब्ध है?  
- उत्तर प्रदेश (1.65 करोड़)
- कुल एमएसएमई ईकाइयों में से 51 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में और 49 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं, लेकिन कुल रोजगार में कितनी हिस्सेदारी शहरी इलाकों की है?  
- 55 प्रतिशत
- भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) का आरंभ कब किया?  
- वर्ष 2007-08 में
- लघु उद्योगों की निरंतर और संगठित उन्नति के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई?  
- वर्ष 1954 में

### औद्योगिक विकास दर एक नजर में

अवधि	खनन क्षेत्र	विनिर्माण	विद्युत क्षेत्र	समग्र रूप में
आधार वर्ष 2004-05				
1995-96	9.7	14.1	8.1	13.0
2000-01	2.8	5.3	4.0	5.0
2001-02	1.2	2.9	3.1	2.7
2006-07	5.4	12.5	7.2	11.6
2007-08	4.9	9.8	7.0	9.2
2008-09	2.6	2.5	2.7	2.5
2010-11	5.2	9.0	5.5	8.2
2011-12	-1.97	3.0	8.2	2.8
2012-13	-2.3	1.3	4.0	1.1
आधार वर्ष 2011-12				
2015-16	4.3	2.8	5.7	3.3
2016-17	5.3	4.4	5.8	4.6
2017-18	2.3	4.6	5.4	4.4
2018-19	2.9	3.9	5.2	3.8
2019-20*	-0.1	0.9	0.8	0.6

**नोट:** औद्योगिक विकास दर को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर आकलित किया जाता है। यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की परिवर्तन दर होती है। \* अप्रैल-नवंबर

### अधिकृत पूंजी

अधिकृत पूंजी (Authorised Capital) किसी कम्पनी की पूंजी की वह अधिकतम मात्रा है, जिस सीमा तक कोई कम्पनी अपने शेयर जारी कर सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि कम्पनी द्वारा जारी किए गए शेयरों का मूल्य अधिकृत पूंजी के बराबर हो। यह अधिकृत पूंजी के बराबर या उससे कम हो सकता है, परंतु अधिक नहीं।

### ले ऑफ

किसी औद्योगिक संस्थान में उत्पादन कम हो जाने या उस वस्तु की मांग कम हो जाने पर कर्मचारियों को नौकरी सेपृथक करना ले ऑफ (Lay Off) कहलाता है।

### विनिवेश

विनिवेश (Disinvestment) से आशय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी अंशधारिता को कम करने या बेचने से है। विनिवेश को निजीकरण की पूर्वपेक्षा माना जाता है। विनिवेश के माध्यम से जब किसी उपक्रम में सरकार की इक्विटी 50 प्रतिशत से कम हो जाती है, तो वह उपक्रम निजी क्षेत्र की कंपनी बन जाती है। भारत में विनिवेश की प्रक्रिया 1991 में शुरू करने का नीतिगत निर्णय लिया गया, परंतु वास्तविक रूप में विनिवेश अप्रैल 1992 में पहली बार हुआ। भारत में विनिवेश का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार करना तथा आधारभूत संरचना क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन एकत्र करना है। अगस्त 1996 में जे.बी. रमकृष्ण की अध्यक्षता में पहला विनिवेश आयोग गठित किया गया था।

### पूंजी उत्पाद अनुपात

उत्पादन की प्रति इकाई के लिए आवश्यक पूंजी या निवेश की मात्रा पूंजी उत्पाद अनुपात (Capital Output Ratio) कहलाती है। यदि उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने के लिए पूंजी की 5 इकाई आवश्यक हो, तो पूंजी उत्पाद अनुपात 5:1 होगा। पूंजी उत्पाद अनुपात तथा पूंजी निर्माण में विपरीत संबंध है। पूंजी उत्पाद अनुपात के अधिक होने पर पूंजी निर्माण कम होता है। फलतः राष्ट्रीय आय कम होगी।

- भारत सरकार के एक उपक्रम के रूप में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? - फरवरी 1955 में
- लघु क्षेत्र तथा अति लघु क्षेत्र की इकाइयों को ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 2000 को प्रधानमंत्री द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? - लघु उद्यमी क्रेडिट गारंटी योजना
- लघु उद्योगों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने वाली एक शीर्ष संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना अप्रैल 1990 में की गई। इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? - लखनऊ
- 1 अक्टूबर, 2000 से सितंबर 2005 तक के लिए लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिकीय उन्नयन के उद्देश्य से कौन-सी योजना शुरू की गई थी? - लघु उद्यमी कैपिटल सन्निडी योजना
- सिडबी के माध्यम से लागू लघु उद्यमी कैपिटल सन्निडी योजना के तहत शुरू में 40 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता था, जिसका 12% सन्निडी के रूप में होता था। परंतु बाद में इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तथा सन्निडी की राशि 15% कर दी गई। इस योजना को बाद में किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया था? - वर्ष 2007
- संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2002 के अनुसार किसी ऐसी कम्पनी को क्या माना जायेगा, जब विगत लगातार 4 वर्षों में से किसी एक वर्ष या एक से अधिक वित्तीय वर्ष के अंत में इसकी संचित हानि इसकी नेट-वर्थ का 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो तथा/अथवा जो लगातार 3 तिमाहियों तक अपने ऋणदाताओं का भुगतान करने में असफल रही हो? - ऋण इकाई
- तिवारी समिति की संस्तुतियों के आधार पर 1985 में ऋण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम (SICA) बनाया गया, जिसके अनुसार मई 1987 में किस बोर्ड का गठन किया गया? - औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR)
- अप्रैल 1993 में औद्योगिक ऋणता की समस्या पर विचार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में बीआईएफआर की भूमिका में बदलाव लाने की संस्तुति की? - ओकरनाथ गोस्वामी समिति
- वर्ष 2000 में गठित इराडी समिति ने बीआईएफआर के स्थान पर किस संस्था के गठन का प्रस्ताव किया? - राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT)
- वर्ष 2002 में संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार गठित राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के पूरे देश में 10 खंडपीठ स्थापित किए गए हैं। इसकी अपीलीय पीठ कहां बनायी गई है? - नई दिल्ली
- एनसीएलटी की अपीलीय पीठ के निर्णयों के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील की जा सकती है? - सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में
- विनिवेश (Disinvestment) वह प्रक्रिया है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सरकारी इक्विटी को बेचा जाता है। इस संबंध में 1991 में किस समिति का गठन किया गया? - रंगराजन समिति
- विनिवेश के माध्यम से जब किसी उपक्रम में सरकार की इक्विटी 50% से कम हो जाती है, तो उस उपक्रम को किस क्षेत्र की कम्पनी माना जाता है? - निजी क्षेत्र
- भारत में विनिवेश की प्रक्रिया 1991 में शुरू करने का नीतिगत निर्णय लिया गया, परंतु वास्तविक रूप में विनिवेश पहली बार कब शुरू हुआ? - अप्रैल 1992 में
- अगस्त 1996 में जे.बी. रामकृष्ण की अध्यक्षता में पहला विनिवेश आयोग गठित किया गया था। दूसरा विनिवेश आयोग जून 2000 में किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? - आर.एच. पाटिल
- 10 दिसंबर, 1999 को केंद्र में एक नए विभाग के रूप में विनिवेश विभाग गठित किया गया। इस मंत्रालय को कब समाप्त कर दिया गया? - मई 2004 में

### ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट

विद्यमान प्लांट के रूपांतरण की अपेक्षा नई जगह पर कारखाने में निवेश करना ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट (Green Field Investment) कहलाता है। इस प्रकार के निवेश से एक ही क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की भीड़-भाड़ एवं संकेंद्रण से होने वाले प्रदूषण एवं अन्य नुकसानों से बचा जा सकता है। वन सम्पदा के अनावश्यक क्षरण को भी इस प्रकार के नव-निवेश से रोका जा सकता है।

### प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

किसी देश के व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा अन्य देश की फर्मों की संपत्ति पर अधिकार अथवा सीधे उत्पादक संस्थाओं में निवेश करना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कहलाता है। इसमें इन संस्थाओं की पूंजी में भागदारी एवं इनको खरीदना सम्मिलित है। निवेशकर्ता को निवेशित पूंजी पर अर्जित लाभों को अपने देश भेजवाने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। वर्ष 2017-18 में 44.85 बिलियन डॉलर की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल इक्विटी अंतर्प्रवाह 44.36 बिलियन डॉलर रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान 44.36 बिलियन डॉलर के एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह में से 70% से अधिक भाग मुख्य रूप से सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, जापान, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों से आया था।

### विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

वित्तीय प्रपत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को सविभाग निवेश (Portfolio Investment) कहते हैं। जब एक देश के निवेशक दूसरे देश की कम्पनियों के अंशों, ऋणपत्रों, बॉन्डों तथा अन्य प्रतिभूतियों में धन लगाते हैं, तो ऐसे निवेश को सविभाग निवेश कहते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में किसी अन्य देश में निवेशकों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियां और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। यह निवेशक को कंपनी की संपत्ति के सीधे स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करता और बाजार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल होता है। इसके विपरीत, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)



## औद्योगिक क्षेत्र

- भारत सरकार ने 4 नवंबर, 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति घोषित की, जिसका लक्ष्य एक दशक के भीतर जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी कितना करना था?  
- **मात्र 25 प्रतिशत**
- भारत सरकार ने अगस्त 2007 में दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) परियोजना को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया। इस परियोजना में सहयोगी देश कौन है?  
- **जापान**
- वर्ष 2017-18 में 44.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल इक्विटी अंतरप्रवाह कितना रहा?  
- **44.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर**
- जुलाई 1997 में सरकार ने 9 केंद्रीय उपक्रमों को **नवरत्न** के रूप में चिह्नित किया। किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसे पहले मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। वर्तमान में (अप्रैल 2018 तक) इन नवरत्नों की संख्या कितनी है?  
- **16**
- अक्टूबर 1997 में सरकार ने लाभ कमाने वाली कम्पनियों को ज्यादा स्वायत्तता देने और अधिकार बढ़ाने का फैसला किया। जो कम्पनी लगातार 3 वर्ष से लाभ कमा रही हो और उसका नेटवर्क सकारात्मक हो; वह ऋणों, व्याज आदि की अदायगी में चूककर्ता न हो; वह बजट सहायता अथवा सरकारी गारंटी के लिए सरकार पर निर्भर न करती हो। ऐसी कंपनियों को **मिनीरत्न** का दर्जा दिया गया। दो वर्गों में विभाजित मिनीरत्नों की वर्तमान (अप्रैल 2018) में कितनी संख्या है?  
- **कुल 75 (वर्ग-1 में 60 और वर्ग-2 में 15)**
- भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यमों को महारत्न का दर्जा मई 2010 में दिया गया। अप्रैल 2018 तक भारत में **महारत्न** सार्वजनिक उद्यमों की संख्या कितनी थी? - **आठ** (बीएचईएल, भारत पेट्रोलियम कॉर. लि., कोल इंडिया लि., गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.)
- सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की अनुरांसा पर 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) की स्थापना की गई। इसके स्वरूप में परिवर्तन कर इसको कब पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बना दिया गया?  
- **जुलाई 1993 में**
- पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के बाद आईएफसीआई दीर्घकालीन ऋण के अलावा और किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराता है?  
- **मध्यमकालीन ऋण**
- निजी क्षेत्र के उद्यमियों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम लि. (ICICI) की स्थापना कब की गई?  
- **जनवरी 1955 में**
- भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड को वर्ष 1997 में निजी क्षेत्र के किस बैंक में विलय कर दिया गया?  
- **आईसीआईसीआई बैंक**
- औद्योगिक क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (**आईडीबीआई**) की स्थापना कब की गई?  
- **19 जुलाई, 1964 को**
- आईडीबीआई को किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक अनुसूचित बैंक घोषित किया गया?  
- **वर्ष 1994**
- राज्यों को लघु एवं मध्यम आकार वाले उद्योगों के विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य वित्त अधिनियम, 1951 के तहत किस संस्था की स्थापना की गई?  
- **राज्य वित्त निगम**
- राज्य वित्त अधिनियम, 1951 के अंतर्गत किस राज्य में सर्वप्रथम राज्य वित्त निगम बनाया गया?  
- **पंजाब**

एक निवेशक को किसी विदेशी देश में प्रत्यक्ष व्यापार व्याज खरीदने की सुविधा देता है। एफडीआई और एफपीआई विदेशी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के सामान्य तरीकों में से एक है। एफपीआई सामान्यतः अल्पकालीन निवेश होता है।

### विशेष आर्थिक क्षेत्र

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ: Special Economic Zones) वे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जिन्हें देश में गैर-विशेष आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। इनमें वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बुनियादी सुविधाएं होती हैं, ये कर मुक्त क्षेत्र होते हैं।

### महारत्न योजना

केंद्र सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2009 में की गई, लेकिन सार्वजनिक उद्यमों को महारत्न का दर्जा मई 2010 में दिया गया। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न बनने के लिए पहले उसे नवरत्न की प्रस्थिति (Status) हासिल करनी होगी, फिर उसका भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना भी आवश्यक है। साथ ही, तीन वर्षों तक कर देने के उपरान्त उसका वार्षिक शुद्ध लाभ 5000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा गत 3 वर्षों के दौरान उसका औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक तथा औसत वार्षिक नेट वर्थ 15,000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए। साथ ही, उसकी उल्लेखनीय वैश्विक उपस्थिति भी होनी चाहिए।

### नवरत्न का मापदंड

किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसे पहले मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अन्य मापदंड इस प्रकार हैं-

- पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान उसका निष्पादन उल्लेखनीय हो।
- अप्रतिष्ठित 6 चयनित मापदंडों में से 60 से अधिक समग्र स्कोर हो। ये 6 मापदंड हैं- निवल मूल्य का शुद्ध लाभ, प्रति शेयर आय, टर्नओवर पर

## मिशन NCERT अर्थव्यवस्था सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- मद्रास राज्य वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसे वर्तमान में तमिलनाडु औद्योगिक वित्त निगम के नाम से जाना जाता है? - वर्ष 1949
- वर्तमान में भारत में 18 राज्य वित्त निगम कार्यरत हैं। इनमें से कितने निगमों की स्थापना 1951 के अधिनियम के तहत हुई है? - मात्र 17
- भारत का एकमात्र राज्य वित्त निगम कौन-सा है, जिसका गठन 1951 के अधिनियम के तहत न होकर कंपनी अधिनियम 1949 के अंतर्गत हुआ है? - तमिलनाडु औद्योगिक वित्त निगम
- 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (IRCI) की स्थापना की गई थी, जिसका नाम 1984 में बदलकर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (IRBI) कर दिया गया। 1 मार्च, 1997 का पुनः इसका पुनर्गठन कर इसका नया नाम क्या रखा गया? - भारतीय औद्योगिक विनियोग बैंक (IIBI) [मुख्यालय- कोलकाता]
- एपरेल पावर्स फॉर एक्सपोर्ट्स स्कीम (APES) और टेक्सटाइल सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट स्कीम (TCIDS) का विलय कर दसवीं पंचवर्षीय योजना में कौन-सी योजना प्रारंभ की गई? - एकीकृत वस्त्रोद्योग पार्क योजना (SITP)
- खादी व ग्रामीण उद्योग आयोग (KVIC) की स्थापना किस वर्ष एक अधिनियम के तहत हुई थी? - वर्ष 1956
- खादी और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से गठित जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? - महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (MGIRI)
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त धनराशि को सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय निवेश निधि का गठन किया गया। इसने काम करना शुरू कब किया? - अक्टूबर 2007 में
- द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में उद्योगों पर बल अधिक दिया गया। किस योजना के आरम्भ तक भारत में केवल उपभोक्ता उद्योग का ही विकास हुआ? - प्रथम
- भिलाई, बोकारो और राउरकेला में सार्वजनिक क्षेत्र में तीन इस्पात कारखानों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषता थी? - द्वितीय योजना
- किस योजना का उद्देश्य आगामी 15 वर्षों में तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना था? - तृतीय योजना
- किस योजना के मध्य तीन वर्ष का योजनावकाश रहा, जिससे औद्योगिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा? - तीसरी व चौथी योजना
- किस योजना में औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य 8-10 प्रतिशत रखा गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर मात्रा 3.9 प्रतिशत रही? - चतुर्थ पंचवर्षीय योजना
- पांचवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य 7% वार्षिक निश्चित किया गया था जबकि वास्तविक वृद्धि दर कितनी प्राप्त हो सकी? - मात्र 5.9%
- पांचवीं योजना में पिछले तीस वर्षों के औद्योगिक विकास का पुनरावलोकन करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन तीस वर्षों में औद्योगिक उत्पादन कितने गुना बढ़ा है? - पांच गुना
- आठवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? - मात्र 7.3 प्रतिशत
- राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति का उद्देश्य पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा मेक इन इंडिया पहल का सहयोग करना है, इसे किस मंत्रालय ने शुरू किया है? - भारी उद्योग विभाग
- चीन के बाद भारत विश्व में रेशम उत्पन्न करने वाला दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन-सा है? - कर्नाटक

ब्याज और करों के पहले का लाभ, नियोजित पूंजी पर चिसावट, ब्याज और करों से पूर्व लाभ, कुल उत्पादन/सेवा लागत और मानव पूंजी का अनुपात तथा अंतरादेशीय निष्पादन।

### मेक इन इंडिया

‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम 25 सितंबर, 2014 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण, अनुसंधान और नव प्रवर्तन का वैश्विक केंद्र तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखला का अभिन्न अंग बनाना है। सरकार ने दस ‘वैश्विक क्षेत्रों’ का पता लगाया है जिनमें वैश्विक चैम्पियन बनने, विनिर्माण में दो अंकों में वृद्धि करने तथा रोजगार के ज्यादा अवसर उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। मेक इन इंडिया संस्करण 2.0 के अंतर्गत नए सिरे से ध्यान देने के लिए पता लगाए गए क्षेत्रों में पूंजीगत वस्तुएं, मोटर वाहन और मोटर वाहनों के पुर्जे, रक्षा और वातावरण, जैव प्रौद्योगिकी, भेषजी और चिकित्सा उपकरण, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम), चमड़ा और फुटवियर, वस्त्र और परिधान, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा, निर्माण, पोत परिवहन और रेलवे शामिल हैं।

### बौद्धिक संपदा अधिकार नीति

मई 2016 में सरकार ने पहली बार बौद्धिक संपदा हेतु भविष्य का खाका तैयार करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति को अंगीकार किया। इसका उद्देश्य भारतीय बौद्धिक संपदा पारितंत्र को सुधारना है। इसमें आशा की गई है कि देश में अभिनव परिवर्तनों का अभियान जन्म लेगा तथा उम्मीद है कि हम ‘रचनात्मक भारत, अभिनव भारत’ की दिशा में अग्रसर होंगे। इस नीति के अनुमोदन और बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) के सृजन के बाद, आईपीआर और पेटेंट संबंधी कार्रवाइयों में पर्याप्त सुधार हुआ है। अप्रैल-अक्टूबर 2017 में 45449 पेटेंट तथा 15627 कॉपीराइट दावा किए गए, जबकि 9847 पेटेंट तथा 3541 कॉपीराइट प्रदान किए गए।



## औद्योगिक क्षेत्र

- भारत के 50 प्रतिशत से अधिक उद्यम पांच राज्यों— तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। सबसे अधिक उद्यम किस राज्य में है?  
- तमिलनाडु
- भारत में कुल श्रम शक्ति का कितने प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में लगा हुआ है?  
- 85 प्रतिशत
- भारत में ई-कॉमर्स उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में इसकी वृद्धि कितनी है?  
- लगभग 60 प्रतिशत से अधिक
- किस समिति की सिफारिशों के आधार पर औषधि विभाग ने बल्क ड्रग नीति का मसौदा जारी किया है?  
- कटोच समिति
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) औद्योगिक निष्पादन का दूसरा पैमाना (पहला सकल मूल्य वर्धित) है। इस आंकड़े को कौन तैयार और जारी करता है?  
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने मई 2017 में आईआईपी के आधार वर्ष को संशोधित करके 2004-05 से क्या कर दिया?  
- वर्ष 2011-12
- आठ मुख्य उद्योगों का सूचकांक कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिकाइनरी उत्पादन, डर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के निष्पादन को आंकता है। ये उद्योग आईआईपी में कितना हिस्सा रखते हैं?  
- मात्र 40 प्रतिशत
- सीएसओ द्वारा जारी वार्षिक राष्ट्रीय आय 2018-19 के अंतिम प्राक्कलनों के अनुसार, वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) औद्योगिक विकास की दर वर्ष 2017-18 में 5.9% की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़कर 6.9% हो गई। प्रथम अग्रिम अनुमान के मुताबिक वर्ष 2019-20 में यह कितनी होगी?  
- मात्र 2.5%
- केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2018-19 में जीवीए में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था?  
- मात्र 29.6 प्रतिशत
- भारत के जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 1950-51 में 16.6 प्रतिशत था। यह वर्ष 2018-19 में बढ़कर कितना हो गया?  
- मात्र 23.1 प्रतिशत
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) औद्योगिक कार्यनिष्पादन का एक माप है जो औद्योगिक विकास की स्थिति पर प्रकाश डालता है। आईआईपी में सर्वाधिक भारांश किस क्षेत्र का होता है?  
- विनिर्माण क्षेत्र (77.63 प्रतिशत)  
(इसके अलावा खनन क्षेत्र को 14.37 प्रतिशत और बिजली क्षेत्र को 7.99 प्रतिशत भारांश प्रदान किया जाता है।)
- आईआईपी के अनुसार, औद्योगिक विकास दर वर्ष 2017-18 में 4.4% की तुलना में वर्ष 2018-19 में 3.8% हो गई। इसके 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में कितना होने का अनुमान है?  
- मात्र 0.6 प्रतिशत
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोक उद्यम विभाग के मुताबिक, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या 339 है, जिनमें से 257 उद्यम प्रचालनिक स्थिति में और 82 उद्यम अप्रचालनिक स्थिति में थे। प्रचालित 257 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से कितने उद्यम लाभ की स्थिति में थे?  
- मात्र 184
- अक्टूबर 2019 में जारी वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत 190 देशों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है?  
- 63वें स्थान पर (2018 में 100वें और 2019 में 77वें स्थान पर)

## स्टार्ट-अप इंडिया

देश के उद्यमी युवाओं के बीच अभिनव परिवर्तन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2015 को 'स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया' पहल की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य उस पारितंत्र को सृजित करना है जो स्टार्ट-अप के विकास के अनुकूल हो। स्टार्ट-अप इंडिया के लिए 19 कार्रवाई बिंदुओं वाली कार्य योजना 16 जनवरी, 2016 को प्रारंभ की गई थी। सरकार ने स्टार्ट-अप पर विनियमकारी बोझ कम करने की जरूरत को स्वीकार किया है और उन्हें 3 श्रम कानूनों और 6 पर्यावरण कानूनों के अंतर्गत स्वयं-प्रमाणित अनुपालन की अनुमति प्रदान की है।

## चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग

भारतीय चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग रोजगार का एक प्रमुख क्षेत्र है। यह फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चमड़े के परिधानों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक और चमड़े के सामान का पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक है।

## भारत के जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान

जीवीए में योगदान (वर्तमान कीमत पर)

सेवा क्षेत्र	57.80%
उद्योग क्षेत्र	28.30%
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	13.90%

जीवीए में योगदान (2011-12 की कीमत पर)

सेवा क्षेत्र	54.15%
उद्योग क्षेत्र	31.46%
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	14.39%

स्त्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

जीडीपी में योगदान (स्त्रोत: सीआईए)

सेवा क्षेत्र	61.5%
उद्योग क्षेत्र	23.0%
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	15.4%

## एस्पायर योजना

प्राद्योगिकी केंद्रों और इन्क्यूबेशन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 16 मार्च, 2015 को नवोन्मेष और ग्रामीण उद्यमी संवर्द्धन योजना (एस्पायर) का शुभारम्भ किया गया, ताकि ग्रामीण और

## निर्णय NCERT अर्थव्यवस्था सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- भारत में मान्यताप्राप्त स्टार्टअप सबसे ज्यादा महाराष्ट्र (18.91%) में स्थापित किए गए हैं। कर्नाटक का स्थान दूसरा (14.67%) और दिल्ली का स्थान तीसरा (13.38%) है। देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप किस क्षेत्र/उद्योग में स्थापित किए गए हैं?

- सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

- वर्ष 2017-18 में 44.85 बिलियन डॉलर की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल इक्विटी अंतरवाह कितना रहा? - 44.36 बिलियन डॉलर

- वैश्विक स्तर पर भारत जापान को पछाड़ते हुए 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (पहला चीन) हो गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान भारत ने कितने कच्चे इस्पात का उत्पादन किया? - 106.56 मिलियन टन

- चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा है। इसकी प्रति व्यक्ति खपत केवल 69 किलोग्राम है, जबकि वैश्विक औसत खपत है?

- 214 किलोग्राम

- रत्न एवं आभूषण क्षेत्र से निर्यात के साथ-साथ रोजगार सृजन में 5 मिलियन का महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। 2017-18 वर्ष के दौरान, रत्न और आभूषण का निर्यात कुल वाणिज्य माल के निर्यात का कितना प्रतिशत था? - मात्र 13.69 प्रतिशत

- भारतीय कपड़ा उद्योग जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है, विनिर्माण में 12.65 प्रतिशत और जीडीपी में 2.3 प्रतिशत का योगदान देता है। कपड़ा और वस्त्र के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा कितना है?

- मात्र 5 प्रतिशत

- कपड़ा और वस्त्र क्षेत्र कृषि के बाद सबसे बड़ा निर्यातक है, जो सीधे तौर पर 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और संबद्ध क्षेत्रों में अन्य 6 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के कुल निर्यात में कपड़ा और वस्त्र का कितना हिस्सा है?

- मात्र 13 प्रतिशत

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को 'मुद्रा बैंक' की शुरुआत की। यहां मुद्रा (MUDRA) का पूरा रूप क्या है? - माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनंस एजेंसी

- 20,000 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ मुद्रा बैंक की स्थापना की गई है। यह बैंक किनको ऋण सहायता मुहैया करायेगा?

- लघु उद्यमों को

- वित्त मंत्रालय ने मुद्रा बैंक को तीन श्रेणियों शिशु, किशोर और तरुण में वर्गीकृत किया है। शिशु श्रेणी के तहत 50,000 रुपये के ऋण दिए जाएंगे। तरुण श्रेणी के उद्यमों को अधिकतम कितना ऋण दिया जायेगा?

- 10 लाख रुपये

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज लेने वालों को एक मुद्रा कार्ड भी मिलेगा, जिसे वे जरूरत पड़ने पर क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। इस कार्ड के जरिये जरूरत पड़ने पर अधिकतम कितनी धनराशि निकाली जा सकेगी? - दस हजार रुपये

- मुद्रा बैंक दूसरी बैंकिंग व वित्तीय एजेंसियों को किस दर पर पुनर्वित्त यानी रीफाइनंस की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा?

- मात्र 7 प्रतिशत

- मुद्रा बैंक को संसद से बिल पारित कराकर बैंक का दर्जा दिया जायेगा। फिलहाल रिजर्व बैंक ने इसको किस तरह का दर्जा दिया है?

- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)

- सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने 4 जुलाई, 2015 को मंगलौर, कर्नाटक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों के लिए रूपे प्लेटफॉर्म पर आधारित मुद्रा कार्ड लांच किया?

- कॉरपोरेशन बैंक

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015' को 2 जुलाई, 2015 मंजूरी दी। इसके पहले ऐसी नीति कितनी बार जारी की गई है?

- एक बार भी नहीं

कृषि आधारित उद्योग में नवोन्मेष और उद्यमिता के लिए स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जा सके।

### संकर वार्षिकी मॉडल (हैम)

हैम ईपीसी (40 प्रतिशत) और बीओटी-वार्षिकी (60 प्रतिशत) मॉडल से मिलकर बना है। सरकार की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण कुल परियोजना लागत का 40 प्रतिशत मौलस्टोन से जुड़ी पांच किस्तों में जारी करता है। शेष 60 प्रतिशत की व्यवस्था निर्माता द्वारा स्वयं की जाती है। निर्माता सामान्यतया परियोजना लागत के 20-25 प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं करता है बल्कि शेष ऋण से जुटाता है।

### औद्योगिक प्रजातंत्र

औद्योगिक प्रजातंत्र (Industrial Democracy) एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है, जिसके तहत किसी औद्योगिक संगठन में श्रमिकों को निर्णय लेने, कार्यस्थल पर जिम्मेदारी का वहन करने और अधिकार को साक्षात् करने का प्रावधान होता है। यह व्यापक सामाजिक उद्देश्य के साथ उच्च औद्योगिक पदानुक्रम के अधिकारियों की शक्तियों और कर्मचारियों के अधिकारों के बीच एक संतुलन का प्रतीक है। यह अवधारणा निरंकुश प्रबंधन या वन-मैन गवर्नेंस की पारंपरिक अवधारणा से पूर्णतः प्रस्थान है। इसमें श्रमिक को उद्यम के जिम्मेदार साझेदार के रूप में माना जाता है।

### बैलेंस शीट

बैलेंस शीट (Balance Sheet) एक ऐसा लेख-पत्र होता है, जिसमें किसी व्यापारिक संस्थान के किसी निश्चित तिथि को समस्त आस्तियों एवं देनदारियों को प्रदर्शित किया जाता है। बैलेंस शीट के आधार पर ही कम्पनी अधवा फर्म की वित्तीय स्थिति का पता लगता है।

### मिश्रित मांग

जब कोई वस्तु एक से अधिक उपयोगों में प्रयोग की जाती है तो ऐसी वस्तु की कुल मांग उसकी विविध उपयोगों हेतु मांग के कुल योग के बराबर होती है। यह कुल मांग मिश्रित मांग (Composite Demand) कहलाती है।